



दैनिक घटती-घटना के कलम बंद अभियान के 28 वें दिन ही सरकार ने खोया आपा...रौंदा संपादक का प्रतिष्ठान व कार्यालय...

- » छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार क्या गैर संवेदनशील सरकार है... ?
- » सरकार को कमियां ना दिखाएं तो क्या दिखाएं... ?
- » क्या विष्णुदेव साय सरकार बेहतर चल रही है...सिर्फ यह बात आईएस लॉबी को पता है...आम जनता को नहीं है जानकारी... ?
- » भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश निर्माण का था जिनका संकल्प,भर्तियों में धांधली की जांच था जिनका संकल्प,अब वह उन्हीं के साथ जिनकी वह कराने वाले थे संकल्प पत्र में वादा कर जांच...
- » किसी का दित्यांग प्रमाण-पत्र फर्जी वह करता है मंत्री के घर मनमर्जी,दित्यांग मांग रहे अधिकार क्या उन्हें दोगे न्याय प्रदेश के कर्णधार ?
- » जिसकी डिग्री है फर्जी जो है...मंत्री का रिश्तेदार क्या उसे बर्खास्त करोगे प्रदेश के कर्णधार... ?
- » क्या फर्जी दित्यांग और फर्जी डिग्री के आधार पर जो कर रहे नौकरी उन्हें होगी जेल...उन्हें मिल सकेगा संकल्प पत्र अनुसार दण्ड... ?

कलम बंद...का उन्चालीसवां दिन

क्या प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के लिए पूरे प्रदेश के लोगों से ऊपर उनके भतीजे हैं? स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों को संरक्षण देने की बात कही...वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर जनसंपर्क अधिकारी को आगे कर समाचार-पत्र पर दबाव बनाने का किया प्रयास...फिर भी नहीं बनी बात तो चलवाया बुलडोजर...ये कैसा संरक्षण?

ये कैसे पत्रकारों की सुरक्षा... कैसे समाचार-पत्र रह सकेंगे निष्पक्ष... जब उन्हें सच लिखने की मिलेगी सजा?

क्या छापें माननीय मुख्यमंत्री जी ?

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महामहिम श्री रमन डेका से हस्तक्षेप की मांग...क्या छापे आयुक्त सहसंचालक आईपीएस मयंक श्रीवास्तव साहब? स्पष्ट कीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी. स्पष्ट कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन. स्पष्ट कीजिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन...गृहमंत्री जी, भारत सरकार क्या छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को लेकर खबर प्रकाशन पर होगी समाचार पत्र पर कार्यवाही?

तुगलकी फरमान के विरुद्ध कलमबंद अभियान...

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के विभाग जनसंपर्क के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री श्री श्यामबिहारी जायसवाल के विभाग से संबंधित समाचारों के प्रकाशन पर जनसंपर्क संचालक के आयुक्त सह संचालक आईपीएस श्री मयंक श्रीवास्तव के मौखिक आदेश पर घटती-घटना के शासकीय विज्ञापन पर रोक लगाकर दबाव बनाने से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के मूलभूत हक पर कुठाराघात के विरुद्ध कलमबंद अभियान...?



घटती-घटना के सही पाठकों,विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

खुला पत्र



-फाइल फोटो-

आखिर कलम बंद करने के लिए एक अखबार को किसने किया मजबूर...

-रवि सिंह-
रायपुर/अम्बिकापुर, 07 अगस्त 2024 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के दैनिक घटती-घटना अखबार को आखिरकार कलम बंद क्यों करना पड़ा..? यह सवाल सभी के जेहन में आ रहा होगा, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि दैनिक घटती-घटना अखबार सदैव ही लोगों के लिए सच्ची खबर प्रकाशित करने का काम करता है...सरकार किसी की भी हो...उन्हें कमियां दिखाने का काम करता रहा है... पिछली सरकार में भी सच लिखने का काम दैनिक घटती-घटना ने किया था, उस समय भी परेशानियों का सामना संपादक सहित पत्रकारों को अखबार के करना पड़ा था, लेकिन उस समय परेशानियों का सामना मुकदमों से करना पड़ा था। कई मामलों

कानूनी दर्ज होने के तौर पर करना पड़ा था। वहीं इस बार आर्थिक क्षति के तौर पर अखबार के संपादक को नुकसान झेलना पड़ा है। भारत के लोकतंत्र में चौथा स्थान पत्रकारिता का आता है जिसे निष्पक्षता के साथ करना अत्यंत जरूरी है, ताकि देश में संतुलन बना रहे। जो काम दैनिक घटती-घटना बखूबी करता भी है, सत्ता परिवर्तन हुआ और नई सत्ता आई पर कमियों को दैनिक घटती-घटना ने प्रकाशित करना शुरू किया, जब पुरानी सरकार की कमियों को प्रकाशित किया गया था तब जनता ने नई सरकार चुनने का फैसला लिया और जब आज नई सरकार जनता के हित के लिए चुनी गई तो आज यह सरकार भी जनता के हित के लिए काम नहीं कर रही है। जिन कमियों को

दिखाने का काम एक बार फिर दैनिक घटती-घटना ने शुरू किया, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो दैनिक घटती-घटना की खबरों की ही देन है उनसे जुड़ी कमियों को अखबार ने जब दिखाना शुरू किया तो उन्हें यह बात रास नहीं आई और उन्होंने अपनी कमियां दूर करने के बजाय दैनिक घटती-घटना को दबाने के लिए उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए शासकीय विज्ञापन पर रोक लगाया जिसका निर्देश उन्होंने मौखिक दिया गया जो न्यायोचित नहीं था और जो शासन की योजनाएं थी उस विज्ञापन को रोकना जो पैसा भी शासन का था ना कि किसी मंत्री या अधिकारी के घर का, विज्ञापन रोकने में भी इतनी तत्परता दिखाई गई की नियमों को भी दरकिनार किया गया, इसके बाद भी

दैनिक घटती-घटना कमियों की खबर प्रकाशित करता रहा, और लोकतंत्र को दबाया ना जाए इसके लिए दैनिक घटती-घटना ने 1 जुलाई से कलम बंद अभियान की शुरुआत की ताकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमेशा ही स्वतंत्रता के साथ काम कर सके। दैनिक घटती-घटना अखबार इस अभियान को सिर्फ अपने लिए शुरू नहीं किया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बचाने के लिए इस अभियान को शुरू किया... ताकि जहां पर प्रेस ऑफ फ्रीडम का स्थान भारत में 169 वां है जो कार्पी शर्मनाक है और इस और देश के सर्वोच्च न्यायालय व देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, और यह भी सोचना चाहिए कि जिस देश में प्रेस ऑफ फ्रीडम की स्थिति अच्छी है वहां पर उस देश की भी स्थिति अच्छी है।

लोकतंत्र पर दबाव बनाने के लिए प्रदेश के शासकीय विज्ञापन की रोक कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कुचलना भी लोगों की आवाज को दबाने का ही प्रयास जैसा है, दैनिक घटती-घटना के कलमबंद अभियान के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री और संयुक्त संचालनालय जनसंपर्क के उपसंचालक मयंक श्रीवास्तव से शासकीय विज्ञापन बंद करने को लेकर सवाल पूछा कि आखिर क्या छोपे जिससे आपको बुरा ना लगे पर यह बात भी सरकार को नागवार गुजरी और सरकार ने और बड़ा कदम उठाया ताकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कुचला जा सके। कलमबंद अभियान के तहत 28 दिनों से प्रदेश के जिम्मेदार व प्रदेश की बेहदरी के लिए जिनके हाथों में कमान है उनसे सवाल

किया गया पर वह सवाल को भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और 28 में दैनिक घटती-घटना के संस्थान पर बुलडोजर चलवा दिया, बुलडोजर चलवाना भले ही लोकतंत्र को कुचलने के लिए आसान लगा हो पर बुलडोजर चलने की आवाज भी पूरे देश में गूज गई पूरे देश में छत्तीसगढ़ सरकार की तानाशाही दिख गई लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास दिख गया, पर नहीं दिख सकी तो सरकार की संवेदना सरकार ने यह बता दिया कि उनके अंदर संवेदना बिल्कुल नहीं है क्योंकि जिस समय कार्यवाही की गई वह समय संपादक के घर पर शोक का था पर शोक के समय में सरकार ने कार्यवाही करके हिंदूवादी पार्टी होने के दावे को भी झुटका दिया। अखबार जो कमियों को दिखा रहा था वह कमी वाकई में सरकार की छवि को

खराब कर रही थी सरकार अखबार की खबरों पर संज्ञान लेकर अपनी छवि को बेहतर कर सकती थी उनके मंत्री अपनी छवि बेहतर करने के बजाय अपनी छवि को और खराब करने का सरकार का प्रयास सरकार के लिए ही गले की फांस बन गई। जो स्वास्थ्य मंत्री का विपक्ष में रहते हुए बड़ नाम था वहीं स्वास्थ्य मंत्री को सत्ता मिलते ही उस नाम को सरे बाजार नीलाम कर लिया और वह भी सिर्फ अपने विवादित कर्मचारी की वजह से यहां तक की संघ को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। इस लेख के माध्यम से हम यह भी जानना चाहेंगे की क्या कलम बंद अभियान चलाकर एक अखबार ने गलत किया या फिर पूरे देश के लोकतंत्र को बचाने का प्रयास किया इस पर आपकी क्या राय है यह भी जरूर दें।



कलम बंद...का उन्चालीसवां दिन



कलम बंद...का उन्चालीसवां दिन



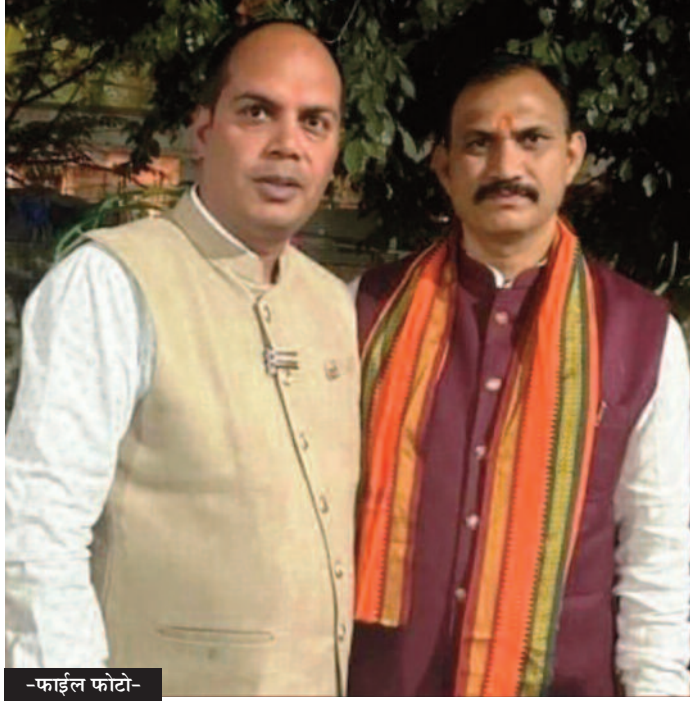
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

खुला पत्र

क्या पुलिस पर दबाव डालकर प्रभारी डीपीएम भतीजे को बचा रहे स्वास्थ्य मंत्री ?

» स्वास्थ्य मंत्री के भतीजे की फर्जी डीपीएम मामले में अभी तक नहीं हुआ मामला दर्ज...
 » शिकायतकर्ता संजय जायसवाल ने स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर की थी कार्यवाही की मांग लेकिन अभी तक नहीं हुई कार्यवाही...
 » अखिर भतीजे ने किस नब्ब को दबा रखा है स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल के...

विश्वविद्यालय ने लिखित में बतलाया है कि वह डीपीएम शिकायतकर्ता द्वारा जारी नहीं की गई है। इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता गांधी नागरिक एकता मंच बैकुंठपुर के अध्यक्ष एवं पार्षद संजय जायसवाल ने सरगुजा पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामला दर्ज करने की मांग की थी लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं किया जा सका है, संभावना जताई जा रही है कि स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल द्वारा भतीजे को बचाने के लिए पुलिस पर भी मामला दर्ज ना करने का दबाव डाला जा रहा है जबकि शिकायतकर्ता ने खुद मंत्री से मिलकर वस्तुस्थिति से अवगत कराया था। ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को माननीय न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा।



-फाइल फोटो-

कराया गया है उससे संपर्क करने पर और रिजल्ट में हस्ताक्षरित रजिस्टार एकसे बतलाया गया कि 2012 से 2014 के गुणा वर्तमान में फर्जी डीपीएम प्रकरण में जेल में हैं। शिकायत के बाद सूरजपुर पुलिस ने

मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच विश्वविद्यालय से कराई जिसके बाद जांच में पाया गया कि प्रिंस जायसवाल की डीपीएम फर्जी है और विश्वविद्यालय से जारी नहीं की गई है। इसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन में डीपीएम फर्जी होने की जानकारी सामने आने के बाद संजय जायसवाल ने स्वास्थ्य मंत्री के भतीजे प्रभारी डीपीएम के खिलाफ एफआईआर करने की मांग सरगुजा पुलिस महानिरीक्षक से की है। उन्होंने महानिरीक्षक को सौंपे ज्ञापन में लिखा है कि उनकी शिकायत पर सूरजपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा 14 जुलाई 2024 को साबरमती विश्वविद्यालय अहमदाबाद गुजरात को डीपीएम की सत्यता को लेकर ईमेल एवं स्प्रीड पोस्ट किया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा 16 जुलाई को ही पुलिस अधीक्षक को डीपीएम फर्जी और कूटचिंत होने की जानकारी दी गई। पत्र में बतलाया गया कि प्रिंस जायसवाल के द्वारा उनके यहां से डीपीएम हासिल नहीं की गई है और इसका कोई रिकार्ड भी विवि के पास उपलब्ध नहीं है। पार्षद ने लिखा है कि विश्वविद्यालय के पत्र के बाद साफ हो गया है कि प्रिंस जायसवाल फर्जी डीपीएम को सेंटर अटैस्ट कर डीपीएम की भर्ती का आवेदन किया था जो कि गैर कानूनी है। पत्र में लिखा गया है कि

भतीजे को बचा कर क्या एहसान चुका रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री ?
 प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को विवादित अफसर और स्टॉफ काफी पसंद हैं उनके द्वारा ऐसे विवादित लोगों को खासा महत्व दिया जाता है। भतीजा काफी विवादित है, पूर्व में कोरिया में पदस्थापना थी कोरोना काल में लूट खसोट कर महारथ हासिल की गई। बाद में कोरिया के तालकालिक कलेक्टर विनय लोह के साथ मिलकर सीटी स्कैन मशीन की खरीदी में काफी लूट-खसोट मचाई गई। कांग्रेस शासनकाल में खुद को कांग्रेसी बतलाने वाले प्रभारी डीपीएम ने राज्य में सत्ता बदलते ही अपना भी सुर बदल लिया और खुद को भाजपाई बतलाने लगा। चाचा प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री बना दिए गए इसलिए उनके नाम का सहारा लेकर अधिकारियों पर भी दबाव बनाने का काम किया जाने लगा। इसी बीच जब कोरिया में आवाज तेज होने लगी तो स्वास्थ्य मंत्री ने भतीजे पर कार्यवाही की बजाए सूरजपुर जिले में प्रभारी डीपीएम बनाकर भेज दिया। अब चुकि वह डीपीएम भी फर्जी बताई गई है जिसके आधार पर प्रभारी डीपीएम ने नौकरी हासिल की है जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या इस पर स्वास्थ्य मंत्री कार्यवाही करेंगे। जानकारी का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री भतीजे प्रभारी डीपीएम पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करेंगे क्योंकि वह उसके एहसान तले दबे हुए हैं।

फिल्तहाल प्रिंस जायसवाल प्रभारी डीपीएम सूरजपुर के रूप में सविदा के रूप में कार्यरत है और इसमें भी फर्जी डीपीएम का प्रयोग किया गया है। पार्षद ने मामले की निष्पक्ष जांच कर एफआईआर दर्ज करने की मांग पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा से 26 जुलाई को किया है लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई और ना ही मामला दर्ज किया गया है जिससे संभावना जताई जा रही है कि भतीजे को बचाने स्वास्थ्य मंत्री द्वारा पुलिस पर भी दबाव डाला जा रहा है। मामले में शिकायतकर्ता संजय जायसवाल ने स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर प्रभारी डीपीएम भतीजे की शिकायत की थी लेकिन लोकतंत्र के चैथे स्तंभ को कुचलने की कोशिश करने वाले स्वास्थ्य मंत्री से ज्यादा उम्मीद करना भी बेमानी है।

प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग खुद वेंटिलेटर पर: दीपक बैज

» कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया आरोप...कहा...नकली दवाओं की सप्लाई के साथ हो रही कमीशनखोरी...



-फाइल फोटो-

रायपुर/अम्बिकापुर, 07 अगस्त 2024 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने गत दिनों वीडियो जारी करते हुए प्रदेश सरकार पर अनेक गंभीर आरोप लगाया है, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर तीखा हमला किया और कहा कि प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग खुद वेंटिलेटर पर है, नकली दवाओं की खरीदी हो रही है, सरकार में कमीशनखोरी होने का आरोप भी कांग्रेस अध्यक्ष ने लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष ने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि स्वास्थ्य विभाग इस सरकार में भगवान भरोसे चल रही है, कहीं डायरिया से मौत, कहीं मलेरिया से मौत, कहीं मशीने बंद पड़ी हुई हैं। कई जगह डॉक्टर नहीं हैं, अंदरूनी क्षेत्रों में स्वास्थ्य अमला नहीं पहुंच पा रहा है। श्री बैज ने कहा कि सरकार पूरी तरह से कमीशनखोरी में लगी हुई है, नकली दवाओं की सप्लाई हो रही है।

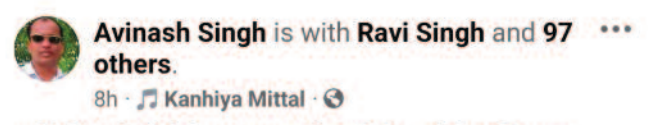
भाजपा सरकार में स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से बदहाल कर दिया गया है, स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ में खुद वेंटिलेटर पर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी विभाग की अध्यक्ष ने सरकार और खासकर स्वास्थ्य विभाग पर भी तीखा हमला किया है जिसके बाद स्पष्ट है कि पूरे प्रदेश भर में विभाग का हाल बेहाल है।

क्या सच कहने वाले कांग्रेस अध्यक्ष पर भी कार्यवाही करेंगे स्वास्थ्य मंत्री ?

प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल को खुद और विभाग की बुराई कर्तई पसंद नहीं है, उन्हे लोकतंत्र के चैथे स्तंभ में वाहवाही पसंद है। यदि चैथे स्तंभ का कोई व्यक्ति विभाग और चिकित्सालयों की दुर्दशा को दिखलाएगा तो यह तय है कि स्वास्थ्य मंत्री द्वारा पहले उसके खिलाफ शिकायत कराई जाएगी और बाद में घटिया स्तर की राजनीति का परिचय देते हुए हर तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की जाएगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज लोकतंत्र का चैथा स्तंभ संघर्ष के दौर से गुजर रहा है, कुछ चाटुकारों ने अपनी कलम गिरवी भी रख दी है, ऐसे चाटुकारों द्वारा वही लिखा जाता है जो पद में बैठे सत्ताधारी पढना चाहते हैं। घटती-घटना अखबार में लगातार दुर्दशा की खबरों का प्रकाशन किया गया जिससे दुर्भावनावाह स्वास्थ्य मंत्री ने संपादक और अखबार को जमींदोज करने का बीड़ा उठाया है, वहीं अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी विभाग की पोल खोली है और बड़ा आरोप लगाया है लगता है स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ भी कोई घडयंत्र कर कार्यवाही कराई जाएगी।

दैनिक घटती-घटना अखबार के संपादक को मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री से जान का खतरा क्यों ?

» सोशल मीडिया में लिखकर संपादक ने जताई आशंका



सूत्रों की माने तो ये पैतरा आजमाने वाले हैं...सूबे के मुखिया व साथी...

मेरे को...या मेरे परिवार को अगर जान और माल का नुकसान होता है तो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय व मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल तथा दो OSD, एक DPM की रहेगी...बयान माने !

संभाग से निकलने वाले दैनिक अखबार के संपादक के व्यावसायिक परिसर पर ऐसे बुलडोजर कार्यवाही होगी वह भी शोक काल में इसकी कल्पना सभ्य समाज कभी नहीं कर सकता। सरकार ने हिंदू मान्यताओं को तोड़ने पर भी मजबूर किया है यह सामान्य विषय नहीं हो सकता। जो राम के नाम का नारा लगाते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, भगवा धारण कर खुद को देश का हितैषी बतलाते फिरते हैं उनके गज में इस प्रकार की घटिया राजनीति का दृश्य देखने को मिला इसकी सर्वत्र निंदा हो रही है। बहरहाल

पिता के शोक कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात अखबार के संपादक ने खुद की जान का खतरा होने का अंदेश व्यक्त किया है, स्पष्ट रूप से सोशल मीडिया में लिखा है कि उनकी जान को खतरा है। अखबार के संपादक अविनाश सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे को...या मेरे परिवार को अगर जान और माल का नुकसान होता है तो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय व मंत्री श्री श्यामबिहारी जायसवाल तथा दो ओएसडी एक डीपीएम की रहेगी...बयान माने। संपादक द्वारा किये गए उक्त पोस्ट के बाद अनेक लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, माना जा रहा है कि संपादक ने जिस प्रकार का अंदेशा व्यक्त किया है उस हिसाब से भविष्य में संपादक को जान का खतरा हो सकता है। संपादक ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि ये पैतरा आजमाने वाले हैं सूबे के मुखिया व स्वास्थ्य मंत्री तथा दो ओएसडी एक डीपीएम की रहेगी...बयान माने।

कलम बंद...का उन्चालीसवां दिन

कलम बंद...का उन्चालीसवां दिन

कलम बंद...

कलम बंद...

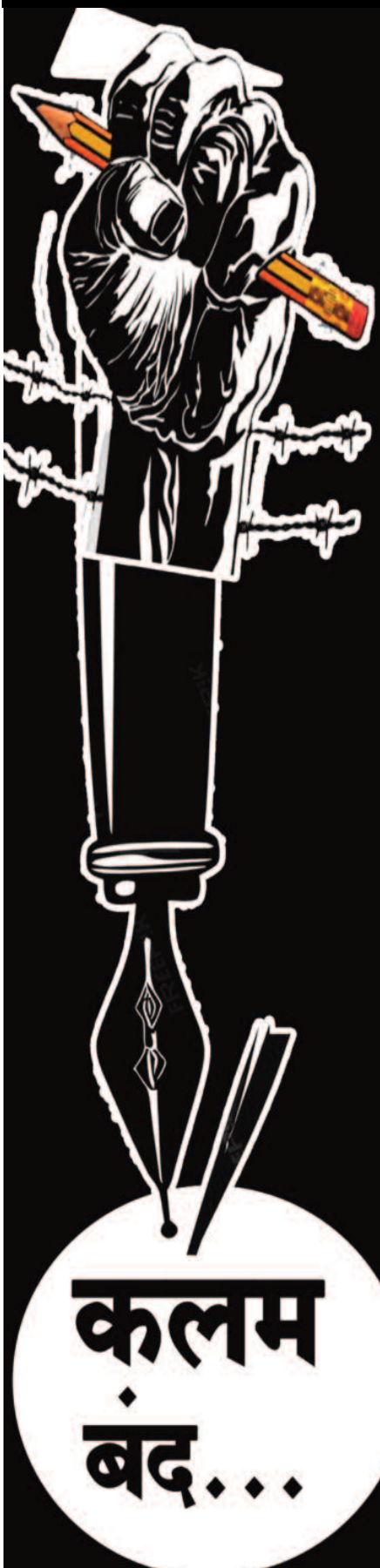
घटती-घटना के सैही पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है... संपादक :- अविनाश कुमार सिंह

खुला पत्र

देश के माननीय प्रधानमंत्री से भी सवाल...क्या भ्रष्टाचार के विरुद्ध छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार के खिलाफ समाचार लिखना है अपराध ?

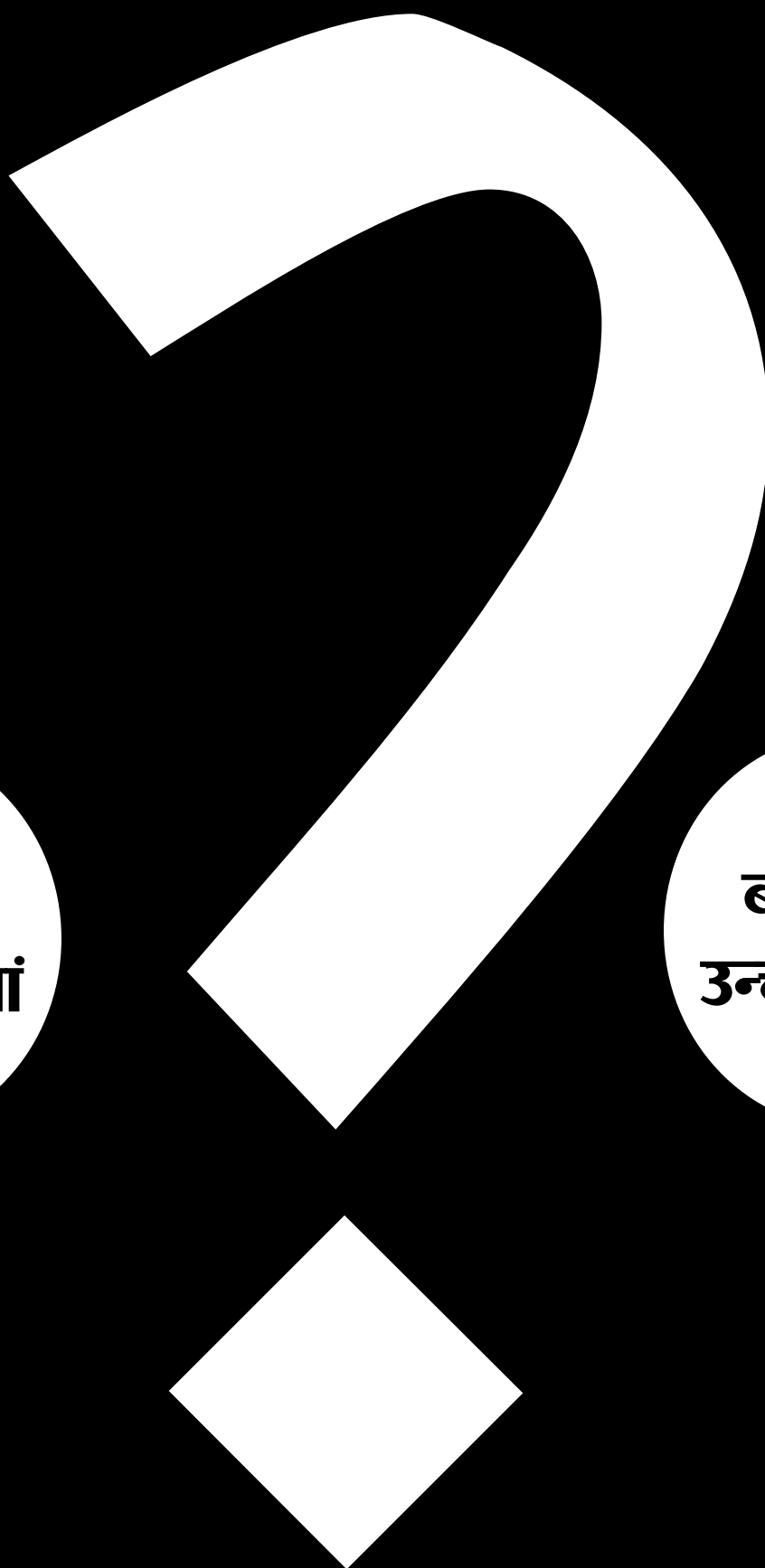
अम्बिकापुर, 07 अगस्त 2024 (घटती-घटना)। माननीय मुख्यमंत्री से भी सवाल है...छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है...केन्द्र में भी आपकी पार्टी की सरकार है...पर छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमियां दिखाने से रोकने का भी प्रयास हो रहा है...यह प्रयास कहीं ना कहीं स्वस्थ लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास है...जहां पर भाजपा सरकार से लोगों को बेहतर करने की उम्मीद होती है तो वहीं पर छत्तीसगढ़ में नवनिर्वाचित मंत्री, विधायक बे-लगाम हो चुके हैं...उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे जिम्मेदारी को निभाने में असमर्थ दिख रहे हैं...उनकी कमियों को बताना उन्हें रास नहीं आ रहा इसलिए वह पत्रकार, संपादक का कलम बंद करने का प्रयास कर रहे हैं अब इस पर आप ही संज्ञान ले...और बताएं की संपादक व पत्रकार कौन सी खबर प्रकाशित करें ?

क्या छापें माननीय मुख्यमंत्री जी ?



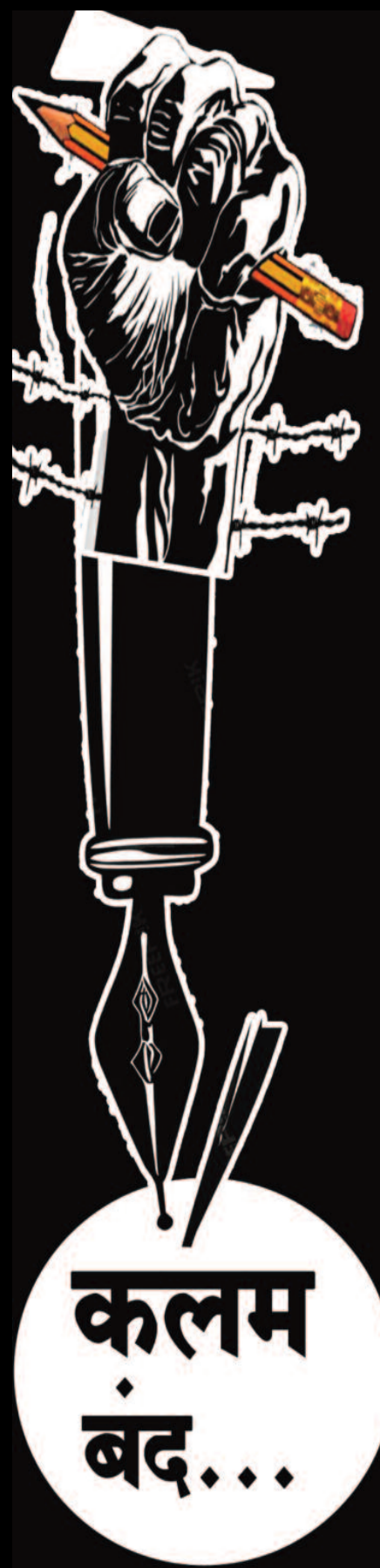
कलम
बंद...का
उन्चालीसवां
दिन

कलम
बंद...



कलम
बंद...का
उन्चालीसवां
दिन

कलम
बंद...



घटती-घटना के सही पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

संपादक :- अविनाश कुमार सिंह

खुला पत्र

भारत में सच्चे पत्रकार को राजनीतिक पार्टियों से खतरा क्यों रहता है ?

अम्बिकापुर, 07 अगस्त 2024 (घटती-घटना) | भारत अपने पत्रकारों को निडर होकर काम करने का स्वतंत्र तरीका प्रदान करने में बहुत पीछे है... इन दिनों... कुछ को छोड़कर... हर दूसरा पत्रकार वही खबर दे रहा है जो सरकार की प्रशंसा करती है... नए चैनल लोगों को सरकार द्वारा की गई गलती से विचलित करने के लिए विभिन्न विषयों पर अनावश्यक बहस दिखाएंगे... इसके कारण, अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो किसी का ध्यान नहीं जाता हैं... दूसरा कारण यह है कि पत्रकार अपने सिद्धांतों और मूल्यों को खो रहे हैं क्योंकि आज स्थिति ऐसी है कि स्थापना के खिलाफ विषयों पर बोलने या लिखने वाले पत्रकारों को धमकी देना, गाली देना और मारना कई अन्य देशों की तरह भारत में भी एक वास्तविकता बन गई है... देश और दुनिया को डरा दिया है... वहीं, पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमलों की घटनाओं ने एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ला दिया है... जो पत्रकार देश और उसके आम नागरिकों के लिए लिखे वे मरे या प्रताड़ित हुए सरकारी तंत्रों के द्वारा...!

क्या छापें माननीय मुख्यमंत्री जी ?



कलम
बंद...

कलम
बंद...का
उन्चालीसवां
दिन

कलम
बंद...का
उन्चालीसवां
दिन

कलम
बंद...

घटती-घटना के सही पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

खुला पत्र

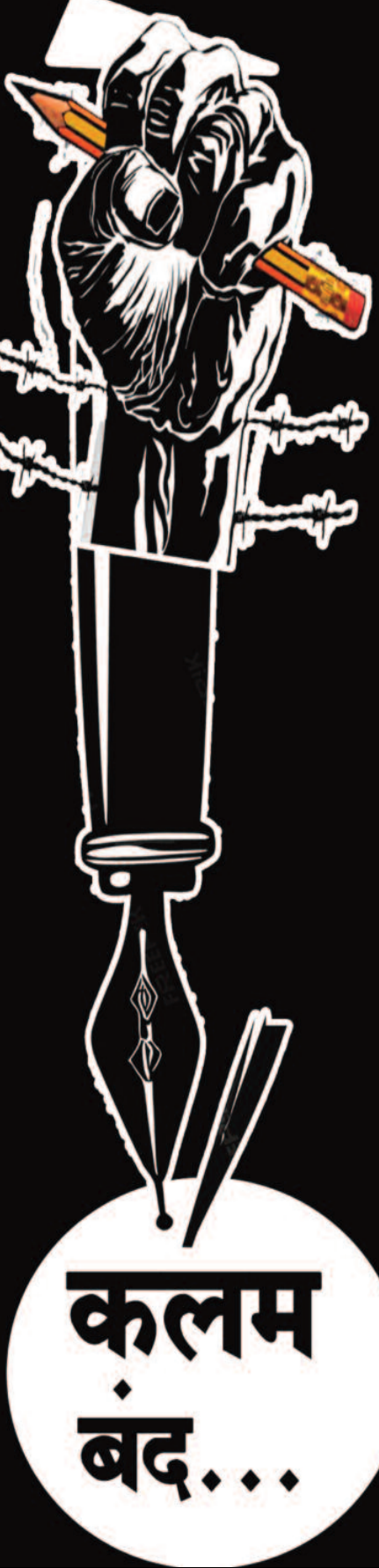
क्या भ्रष्टाचार का मामला वहीं होगा दर्ज जहां होगी भाजपा से इतर दल की सरकार ?

- » भ्रष्टाचार की खबरों से दिक्कत...
- » कमी दिखाओ तो दिक्कत...
- » जनता की परेशानियों को दिखाओ तो दिक्कत...

अम्बिकापुर, 07 अगस्त 2024(घटती-घटना)।
आखिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ करें तो क्या

करें ? सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने पत्रकार दौड़ रहा पर पत्रकार की दौड़ के पीछे निर्वाचित जनप्रतिनिधि उसकी दौड़ की गति को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता रहे पर पत्रकार ना दिखाएं क्या यही चाहता है जनप्रतिनिधि या फिर सरकारी तंत्र।

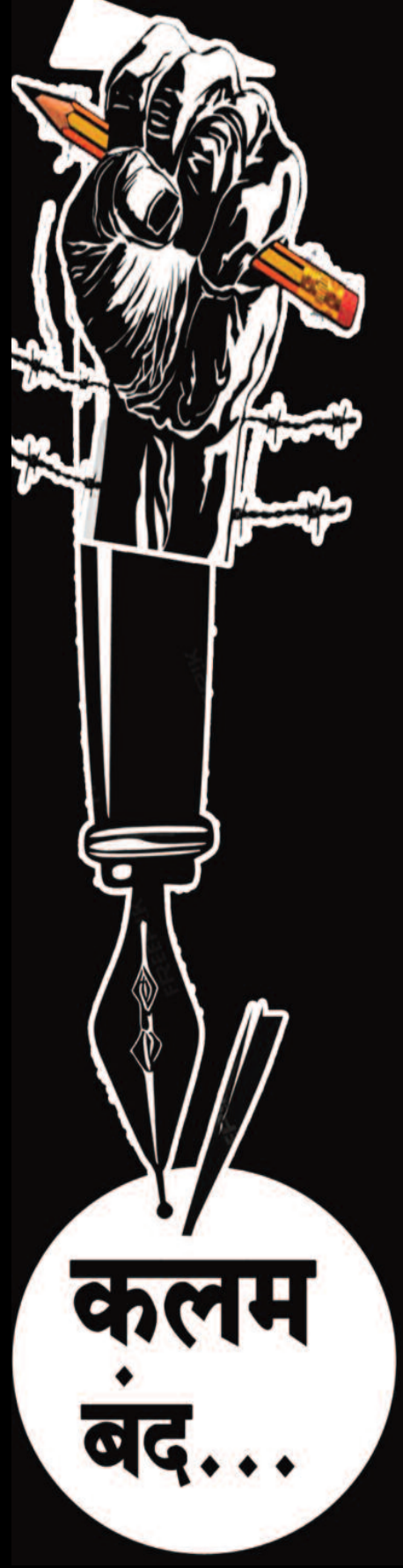
क्या छापें माननीय मुख्यमंत्री जी ?



कलम बंद...

कलम बंद...का उन्चालीसवां दिन

कलम बंद...का उन्चालीसवां दिन



कलम बंद...

घटती-घटना के सही पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

संपादक :- अविनाश कुमार सिंह

खुला पत्र

तुगलकी फरमान के विरुद्ध कलमबंद अभियान

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के विभाग जनसंपर्क के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री श्री श्यामबिहारी जायसवाल के विभाग के संबंधित समाचारों के प्रकाशन पर जनसंपर्क संचालक के आयुक्त सह संचालक आईपीएस श्री मयंक श्रीवास्तव के मौखिक आदेश पर घटती-घटना के शासकीय विज्ञापन पर रोक लगाकर दबाव बनाने से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के मूलभूत हक पर कुठाराघात के विरुद्ध कलमबंद अभियान...के पन्द्रहवें दिन भी केंद्र सरकार से अनुमोदित विज्ञापन नियमावली के आदेश को ठेंगा दिखाने वाले जनसंपर्क विभाग के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं देने के पीछे किसका हाथ...

क्या छापें स्वास्थ्य मंत्री जी ?

क्या छापें आयुक्त सहसंचालक आईपीएस मयंक श्रीवास्तव जी ?



क्यों न लिखें सच ?

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी 25 जून को संविधान हत्या दिवस छत्तीसगढ़ में नहीं मनाया जायेगा क्या ?

इमरजेंसी पर बात...हर बात पर आरोप...तो छत्तीसगढ़ में एक आईपीएस के तुगलकी

फरमान पर आदिवासी अंचल से विगत 20 वर्षों से प्रकाशित अखबार

पर क्यों किया जा रहा है जुर्म... ?

क्यों कलमबंद आंदोलन के लिए विवश होना पड़ा एक दैनिक अखबार को... ?

संविधान हत्या दिवस 25 जून
क्या छत्तीसगढ़ में भी मनेगा ?

छत्तीसगढ़ सरकार घर तोड़िए या
कार्यालय तोड़िए...इंकलाब होता
रहेगा इंसाफ तक...

अब तो बताईए मुख्यमंत्री जी...क्या छापें ?

घटती-घटना के सही पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

संपादक :- अविनाश कुमार सिंह